



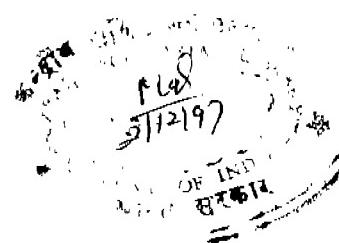
भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 413]
No. 413]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 20, 1997/आश्विन 28, 1919
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 20, 1997/ASVINA 28, 1919

वित्त मंत्रालय

(केंद्रीय कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 1997

सा. का. नि. 603 (अ).—केन्द्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 637 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि :—

(क) उक्त अधिनियम की धारा 620 के अधीन निधि या पारस्परिक फायदा सोसाइटी के रूप में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पूर्व घोषित कोई भी कंपनी (जिसे इसमें इसके पश्चात् ऐसी निधि या पारस्परिक फायदा सोसाइटी कहा गया है) इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् :—

(i) इसके सदस्यों द्वारा इसके पास रखी गई किसी प्रकार की प्रतिभूति को गिरवी नहीं रखेगी ;

(ii) किसी उधार लेने वाले को 7.5 लाख रुपए या कंपनी के कुल निक्षेपों के एक प्रतिशत से अधिक, जो भी कम हो, ऋण या अग्रिम नहीं देगी ;

(ख) प्रत्येक ऐसी कोई निधि या पारस्परिक फायदा सोसाइटी, इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् :—

(i) यह सुनिश्चित करेगी कि इसकी शुद्ध स्थानिकाधीन निधि और इसके अधिमानी शेयर पूँजी का योग दस लाख रुपए या ऐसी उच्चतर रकम से कम है, जो केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें ;

परन्तु विद्यमान निधियां या पारस्परिक फायदा सोसाइटियों को निम्नलिखित समय के भीतर दस लाख रुपए की उक्त न्यूनतम रकम को प्राप्त करने के लिए समय दिया जाएगा —

(अ) इस अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि ; या

(आ) ऐसी अंतरिक्त अवधि, जिसनी केन्द्रीय सरकार, ऐसा करने के लिए कारणों को अभिलिखित किए जाने के पश्चात् बढ़ाए :

परन्तु यह और कि जब कुल शुद्ध स्वामित्वाधीन निधि और अधिमानी शेयर पूँजी की न्यूनतम सीमा भविष्य में दस लाख रुपए से अधिक बढ़ा दी जाती है तो निधियों और पारस्परिक फायदा सोसाइटियों को ऐसे कुल योग को बढ़ाने के लिए उचित समय दिया जाएगा ; और

(ii) यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसी निधि या पारस्परिक फायदा सोसाइटी द्वारा स्वीकृत निष्क्रेपों और दिए गए ऋणों के संबंध में ब्याज की दरें, ऐसे विनियमों के अनुरूप हैं, जो समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाएं।

स्पष्टीकरण —

“शुद्ध स्वामित्वाधीन निधि”

का वही अर्थ होगा तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में इसके लिए दिया गया है।

2. इस अधिसूचना के खंड (क) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) तथा खंड (ख) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट निर्देश, इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात् जहां तक संभव हो, उक्त अधिनियम की धारा 620 के अधीन निधि या पारस्परिक फायदा सोसाइटी के रूप में घोषित प्रत्येक कंपनी को लागू होंगे।

[फा. सं. 37/61/96-सी. एल. III (क)]

जैन्दर सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 1997

G.S.R 603 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 637A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby directs that —

(a) no company declared as a Nidhi or Mutual Benefit Society under Section 620A of the said Act, before the date of this notification (hereinafter referred to as such Nidhi or Mutual Benefit Society) shall, after the publication of this notification :—

- (i) pledge any type of security lodged with it by its members ; and
- (ii) give to any borrower loans or advances exceeding Rs. 7.5 lakhs or one per cent of the total deposits of the company, whichever is less ;

(b) every such Nidhi or Mutual Benefit Society shall, after the publication of this notification --

- (i) ensure that the total of its net owned fund and its preference share capital is not less than ten lakh rupees or such higher amount as the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, may specify from time to time :

Provided that the existing Nidhis or Mutual Benefit Societies shall be given time to reach the said minimum amount of ten lakh rupees within —

- (A) a period of three years from the date of this notification : or
- (B) such further period as the Central Government may, after recording the reasons in writing for so doing, extend :

Provided further that when the minimum limit of the total net owned fund and preference share capital is enhanced beyond ten lakh rupees in future, the Nidhis and Mutual Benefit Societies shall be given reasonable time to augment such total ; and

- (ii) ensure that interest rates on deposits accepted by and loans given by such Nidhi or Mutual Benefit Societies are in conformity with such regulations that may be issued by the Reserve Bank of India, from time to time.

Explanation —

“Net owned fund”

shall have the same meaning as assigned to it in the Reserve Bank of India Act, 1934.

2. The directions specified in sub-clauses (i) and (ii) of clause (a) and sub-clauses (i) and (ii) of clause (b) of this notification shall, as far as may be, apply to every company declared as a Nidhi or Mutual Benefit Society under Section 620A of the said Act on or after the publication of this notification.

[File No. 37/61/96-CL III (a)]

JAINDER SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 1997

सा. का. नि. 604 (अ).—केंद्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 637 के उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई अधिसूचना सं. सा. का. नि. 241, तारीख 28 अप्रैल, 1995 और अधिसूचना सं. सा. का. नि. 773 (अ), तारीख 4 दिसम्बर, 1995 में निम्नलिखित उपान्तरण करती हैः—

भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा. का. नि. 241, तारीख 28 अप्रैल, 1995 में किसी निधि के सदस्यों से संबंधित मद (ख) की उप-मद (i) के स्थान पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

(i) कम से कम दो हजार सदस्य :

परन्तु विद्यमान निधियों और पारस्परिक फायदा सोसाइटियों को अपनी न्यूनतम सदस्य संख्या को एक हजार से बढ़ाकर दो हजार से अन्यून करने के लिए इस अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष का समय दिया जाएगा।

भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा. का. नि. 773 (अ) तारीख 4 दिसम्बर, 1995 में मद (क) की उप-मद (vi) का इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 37/61/96-सी. एल. III]

जैन्दर सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 1997

G.S.R. 604 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 637A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government makes the following modifications in the notifications GSR 241 dated 28th April, 1995 and GSR 773 (E) dated 4th December, 1995 as follows :—

In the notification number GSR 241 dated 28th April, 1995 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i), in item (b) for sub-item (i) relating to the members of a nidhi the following sub-item shall be substituted with effect from the date of the publication of this notification in the Official Gazette namely :—

(i) at least two thousand members ;

Provided that existing Nidhis and Mutual Benefit Societies shall be given one year's time from the date of this notification to increase the membership from not less than one thousand to not less than two thousand members.

In the notification number GSR 773 (E) dated 4th December, 1995 published in the Gazette of India (Extraordinary), Part II, Section 3 Sub-section (i), in item (a) sub-item (vi) shall be omitted with effect from the date of the publication of this notification in the Official Gazette.

[File No. 37/61/96-CL III]

JAINDER SINGH, Lt. Secy.